Part XX: Amendment of the Constitution

Part XX of the Constitution of India deals with the Amendment of the Constitution. It lays down the procedure for amending the provisions of the Constitution.

Article 368 provides for the power of Parliament to amend the Constitution and lays down the procedure for amendment of the Constitution. The procedure involves the introduction of a bill in either House of Parliament, with a two-thirds majority of the members present and voting, and ratification by the legislatures of not less than one-half of the States.

The amendment can relate to any provision of the Constitution, including the fundamental rights, the directive principles, and the federal structure of the Constitution. However, some provisions of the Constitution, such as the basic structure, are beyond the power of Parliament to amend.

Overall, Part XX of the Constitution of India lays down the procedure for amending the provisions of the Constitution and provides for the power of Parliament to do so. It ensures the flexibility of the Constitution and enables it to adapt to changing circumstances while preserving its basic structure and principles.

भाग XX: संविधान का संशोधन

भारत के संविधान का भाग XX संविधान के संशोधन से संबंधित है। यह संविधान के प्रावधानों में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।

अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति प्रदान करता है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया में संसद के किसी भी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ एक बिल पेश करना और कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन शामिल है।

संशोधन संविधान के किसी भी प्रावधान से संबंधित हो सकता है, जिसमें मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत और संविधान की संघीय संरचना शामिल है। हालाँकि, संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे कि मूल संरचना, संशोधन करने की संसद की शक्ति से परे हैं।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XX संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और ऐसा करने के लिए संसद की शक्ति प्रदान करता है। यह संविधान के लचीलेपन को सुनिश्चित करता है और इसकी बुनियादी संरचना और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए इसे बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है।